

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0.

// विविध आदेश //

क्रमांक-क्यू/विविध/2021

विदिशा दिनांक 24.04.2021

माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा द्वारा जारी आदेश क्र0-क्यू-3/एस.डब्ल्यू/2021/5026, विदिशा, दिनांक 23.04.21 द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्र0 क्यू-3/एस.डब्ल्यू/2021/4915, दिनांक 17.04.21 से कोरोना कर्फ्य दिनांक 26.04.21 प्रभावी किया था, को दिनांक 30.04.2021 तक प्रभावी किया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी एस0ओ0पी0 क्रं0 ए/113 दिनांक 15.01.2021 की कंडिका क्र0-06 व 17 एवं एसओपी क्र0 ए/1149, दिनांक 03.04.21 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुये, शासन के उक्त आदेश तथा पक्षकारों, साक्षियों की सुविधा तथा कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से कार्यालय विविध आदेश क्र0 क्यू/विविध/21, दिनांक 18.04.21 में निम्नानुसार यथानिर्देश संशोधन आदेश जारी किये जाते हैं:—

01. दिनांक 30.04.21 तक जिला न्यायालय विदिशा, कुटुम्ब न्यायालय विदिशा सहित समस्त तहसील मुख्यालय में नियमित सुनवाई निलंबित रहेगी।

02. उपरोक्त अवधि में अत्यावश्यक प्रकृति (जैसे-जमानत, रिमाण्ड एवं सुपुर्दगी आदि) के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग (वर्चुअल मोड) के माध्यम से सुनवाई की जावेगी।

03. दिनांक 27.04.21 से 30.04.21 को नियत समस्त प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई उसी स्थिति में निम्नानुसार सुनवाई हेतु लिये जावेंगे।

क्रं0	पूर्व में नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	27/04/21	12/05/21
2	28/04/21	13/05/21
3	29/04/21	17/05/21
4	30/04/21	18/05/21

साथ ही समस्त न्यायिक अधिकारियों को यह भी यथानिर्देशित किया जाता है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से समय आबंधित/निर्देशित प्रकरणों (Time Limit & Others) की सुनवाई हेतु आगामी तिथि अपने विवेकानुसार निर्धारित कर, उक्त संबंध में पृथक से कार्यवाही करेंगे।

04. उपरोक्त अवधि में पक्षकारगण का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

05. अधिवक्तागण वीडियो कांफ्रेंसिंग/जिट्सी मीट एप्प के माध्यम से एवं न्यायालय परिसर में स्थापित व्ही0सी0 पाईट के माध्यम से उपस्थित हो सकेंगे तथा अत्यावश्यक मामलों के आवेदन पत्र ई-मेल dcourtvid-mp@nic.in के माध्यम से भेज सकेंगे।

06. किसी कारणवश वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई नहीं होने पर एक समय में एक ही अधिवक्ता मॉस्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करते हुये ही भौतिक रूप से सुनवाई हेतु न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे।

07. अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई से संबंधित जानकारी हेतु श्री राजेंद्र पाल बतरा, प्रशासनिक अधिकारी मोबाईल नंबर 94253-35553, श्री प्रेमनारायण गढ़वाल उप प्रशासनिक अधिकारी मोबाईल नंबर 98270-85281 एवं श्री राजीव चतुर्वेदी, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट मोबाईल नंबर 99778-23929 से संपर्क किया जा सकता है साथ ही जिला न्यायालय विदिशा की ई-मेल dcourtvid-mp@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।
08. प्रत्येक न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने न्यायालय में प्रकरणों की आगामी तिथि को नियत कर, न्यायालय के सूचना पटल पर जानकारी चरपा करेंगे और साथ ही सीआईएस सॉफ्टवेयर पर प्रकरणों की आगामी तिथि को आवश्यक रूप से अपलोड कराने हेतु न्यायालय के किसी भी एक रीडर (सिविल या किमीनल) को निर्देश देवें।
09. न्यायालय में अत्यावश्यक ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले समस्त न्यायिक अधिकारी/कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण मॉस्क, सैनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
10. समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्यालय में पर उपस्थित रहेंगे और अपने-अपने मोबाईल चालू रखेंगे और सूचित किये जाने पर तत्काल आदेशानुसार उपस्थित होंगे। किसी भी न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी का मोबाईल बंद होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
11. कोई न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और अनुमति उपरांत मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मुख्यालय पर उपस्थिति के उपरांत पूर्व में जारी विविध आदेश क्र० क्यू/एस डब्ल्यू/21, दिनांक 06.04.21 के भाग-दो के पैरा क्र०-3 के अनुसार RT-PCR Test एवं सात दिवस के होम क्वारंटाईन अवधि के उपरांत उपस्थित होंगे।
12. किसी भी न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी के स्वयं या परिवारजन की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने की दशा में पूर्व में जारी विविध आदेश क्र० 1182, दिनांक 09.04.21 के पालन में इस स्थापना हेतु नियुक्त Covid Protocol Officer's मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विदिशा श्री संदीप कुमार जैन मोबाईल नंबर 94250-82298 एवं जिला रजिस्ट्रार डॉ०रविकांत सोलंकी को जांच रिपोर्ट एवं आवेदन पत्र सहित तत्काल सूचित करेंगे।
13. समस्त न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय, केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों/विविध आदेशों और गार्ड लाईनों का कड़ाई से पालन करेंगे।
14. श्री ठाकुर दयाल सिंह एस०ए० सहित समस्त आई०टी०अस्सिस्टेंट जिला न्यायालय एवं तहसील मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिदिन जिला न्यायालय की ई-मेल dcourtvid-mp@nic.in पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों वाले आवेदन सहित माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य महत्वपूर्ण सहित समस्त मेल आदि का प्रिंट निकालकर संबंधित न्यायालय को सूचित करेंगे।
15. समस्त प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि/अभिलेखागार अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे अत्यंत आवश्यक प्रकृति के प्रतिलिपि/अभिलेखागार आवेदन

मांग पत्र के निराकरण हेतु प्रतिलिपि/अभिलेखागार अनुभाग के संबंधित कर्मचारी को निर्देशित कर, आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

16. समस्त प्रभारी अधिकारी तलवाना अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अवधि में आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों और समयावधि में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों के सीआईएस सॉफ्टवेयर में दर्ज करने हेतु, संबंधित कर्मचारी की ड्यूटी लगावें।

17. पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जावे कि संबंधित केस डायरी स्कैन कर न्यायालय को ई-मेल आईडी पर रिमाण्ड अवधि के पूर्व निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करें। यदि किन्हीं कारणों से केस डायरी मेल आई डी पर प्राप्त नहीं हो सके तो संबंधित न्यायालय के रीडर/प्रस्तुतकार दस्ताने (ग्लब्स) पहनकर ही उपरोक्त केस डायरी प्राप्त करेंगे और संबंधित न्यायिक अधिकारी भी दस्ताने (ग्लब्स) पहनकर ही केस डायरी का अवलोकन व कार्य करेंगे।

18. उपरोक्त दिवसों में नियमित न्यायिक कार्यवाहियों के निलंबित रहने की दशा में अत्यावश्यक प्रकृति (जैसे-जमानत, रिमाण्ड एवं सुपुर्दगी आदि) के प्रकरणों की सुनवाई हेतु निम्नानुसार सारणी में वर्णित अपर सत्र न्यायाधीश को सुबह 11:00बजे से 02:00बजे तक एवं जेएमएफसी दोपहर 02:00बजे से शाम 05:00 बजे तक उनके स्टॉफ सहित ड्यूटी लगाई जाती है।

1. जिला न्यायालय विदिशा:—

क्रं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	27 अप्रैल 21	श्री आत्माराम टांक, IASJ	सुश्री आरती गौतम, जेएमएफसी
2	28 अप्रैल 21	श्री आत्माराम टांक, IASJ	सुश्री अनुप्रिया पाराशर, जेएमएफसी
3	29 अप्रैल 21	श्री आत्माराम टांक, IASJ	श्री अभिजीत सिंह, जेएमएफसी
4	30 अप्रैल 21	श्री आत्माराम टांक, IASJ	सुश्री सोनल गुप्ता, जेएमएफसी

2. तहसील मुख्यालय गंजबासौदा :—

क्रं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	27 अप्रैल 21	श्री सतीशचंद्र मालवीय, III ASJ	श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, जेएमएफसी
2	28 अप्रैल 21	श्री विनोद शर्मा, IASJ	श्रीमती सपना शर्मा, जेएमएफसी
3	29 अप्रैल 21	श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, Add. ASJ	श्री राकेश शर्मा, जेएमएफसी
4	30 अप्रैल 21	श्री सतीशचंद्र मालवीय, III ASJ	श्री राहुल निरंकारी, जेएमएफसी

3. तहसील मुख्यालय सिरोंज :—

क्रं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	27 अप्रैल 21	श्री अमजद अली, IIASJ	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी
2	28 अप्रैल 21	श्री अमजद अली, IIASJ	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी
3	29 अप्रैल 21	श्री अमजद अली, IIASJ	श्री दिलीप पाटिल, जेएमएफसी
4	30 अप्रैल 21	श्री अमजद अली, IIASJ	श्री दिलीप पाटिल, जेएमएफसी

4. तहसील मुख्यालय कुरवाई :—

कं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	27 अप्रैल 21	---	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
2	28 अप्रैल 21	---	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
3	29 अप्रैल 21	---	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
4	30 अप्रैल 21	---	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी

5. तहसील मुख्यालय लटेरी :—

कं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	27 अप्रैल 21	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, ASJ, लटेरी	श्री देवेन्द्र सोलंकी, जेएमएफसी
2	28 अप्रैल 21	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, ASJ, लटेरी	श्री देवेन्द्र सोलंकी, जेएमएफसी
3	29 अप्रैल 21	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, ASJ, लटेरी	श्री देवेन्द्र सोलंकी, जेएमएफसी
4	30 अप्रैल 21	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, ASJ, लटेरी	श्री देवेन्द्र सोलंकी, जेएमएफसी

वास्ते—जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा

पृष्ठांक-626 / विविध / 2021
प्रतिलिपि-1207

विदिशा, दिनांक 24.04.2021

- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ.
- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.
- समस्त न्यायिक अधिकारी / प्रभारी अधिकारी नजारात अनुभाग एवं समस्त न्यायिक कर्मचारीगण— विदिशा / गंजबासौदा / सिरोंज / कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विदिशा,
- पुलिस अधीक्षक, विदिशा
- जेल अधीक्षक जिला जेल एवं उपजेल गंजबासौदा / लटेरी
- कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी विदिशा
- अध्यक्ष अभिभाषक संघ विदिशा / गंजबासौदा / सिरोंज / कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- प्रिंट मीडिया / न्यूज मीडिया प्रभारी विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं सूचना प्रसारित किये जाने हेतु।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट / असिस्टेंट को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश जिला न्यायालय विदिशा की वेबसाइट पर अपलोड करें।

वास्ते—जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

W.P. No. 8820/2021

[In Reference (Suo Motu) vs. Union of India and others]

1

Jabalpur, Dated: 23.04.2021

Heard through Video Conferencing.

Shri P.K. Kaurav, Advocate General and Shri Pushpendra Yadav, Additional Advocate General for the State.

Shri J.K. Jain, Assistant Solicitor General for the Union of India.

Dr. Vijay Kumar Chaudhary, Advocate - Chairman, M.P. State Bar Council.

Shri Raman Patel, Advocate - President, High Court Bar Association, Jabalpur.

Shri Manoj Sharma, Advocate - President, High Court Advocates' Bar Association, Jabalpur.

Shri Aditya Adhikari, Senior Advocate - Secretary, Senior Advocates' Council, Jabalpur.

Shri Lokesh R. Bhatnagar, Advocate - President, High Court Bar Association, Indore.

Shri M.P.S. Raghuvanshi, Advocate - President, High Court Bar Association, Gwalior.

We have initiated this *suo motu* proceeding in an extraordinary situation on account of surge in Coronavirus cases in the State following the onset of second Covid wave, as a result of which, the residents of Madhya Pradesh are facing acute crisis. The State Government has imposed lockdown/corona curfew in almost all major cities of the State, mostly starting from 10.04.2021 ending on different dates, at most of the places either on 26.04.2021 or on 30.04.2021. Considering the spike in Coronavirus cases, situation is not likely to

be normal in next few weeks. Resumption of normal work by the Courts in the State is likely to take some time.

A large number of Coronavirus positive cases are being reported from different parts of the State including bigger cities like Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Ujjain. In fact, Corona has engulfed substantial part of the State and has made inroads even into rural areas. Although we do not want to disclose the exact numbers collated by the Registry of this Court but suffice it to say that a large number of stakeholders including the Judicial Officers, employees of the Courts and the Advocates have been found positive for Coronavirus in almost all the districts of the State and unfortunately, some of them have even succumbed to this deadly disease. Owing to this situation, the functioning of the Courts everywhere has been affected adversely. More or less, all the District and Sub-ordinate Courts are working in a restricted manner and taking up only extremely urgent nature of cases by deputing small number of officers by rotation through virtual mode. In certain places, where Coronavirus cases were relatively lesser in number, the work was being carried out hitherto through hybrid mode both by physical appearance as well as virtual appearance but working of the Courts even at such places has been affected adversely and only extremely urgent nature of cases are being taken up by deputing limited number of officers. The State Government in the recent order issued on 20.4.2021 required all the Government offices to function with only 10% staff members up to 30.4.2021, however with the exception of offices pertaining to essential services. The offices of the Courts have not been kept out of purview of the aforesaid restriction. Now therefore in view of recent order issued by the Government on 20.4.2021, the District and Sub-ordinate Courts at other places of the State are also shifting to virtual mode.

It would be evident from above narration that the Courts throughout the State are not able to function effectively in a regular manner. Even the High Court, Principal Seat at Jabalpur, Bench at Indore and also Bench at Gwalior had to suspend the normal

functioning following lockdown imposed by the Government with effect from 10.4.2021. It may take some more time for the High Court as well as District and Sub-ordinate Courts, Labour Courts and Family Courts in the State to resume normal functioning due to the ongoing unprecedented crisis. This has given rise to a situation where most of the litigants are not in a position to approach the Courts. Though some of them may stay in touch with their advocates only telephonically but majority of them may not be in a position to contact their advocates. Many of the matters which otherwise would have been listed for passing appropriate orders, owing to aforementioned reasons, are not being taken up by different Courts.

In view of above, therefore, with a view to ensuring that the citizens of the State in general and the litigants before the Courts in particular, do not suffer on account of their inability to approach the Courts of law, this Court proposes to invoke its extraordinary power under Article 226 and its power of superintendence under Article 227 of the Constitution of India and also inherent power over the criminal matters under Section 482 of the Code of Criminal Procedure, power of superintendence over Criminal Courts under Section 483 of the Code of Criminal Procedure and inherent power over the civil matters under Section 151 of the Code of Civil Procedure and issue the following directions to remain operative in the first phase till 15th June, 2021:-

- (i) that all the interim orders/directions issued or protection granted including any order requiring any compliance by the parties to such proceedings, passed by this Court or any other Court sub-ordinate to it or any Family Court or Labour Court or any Tribunal or any other Judicial or Quasi Judicial forum in the State of Madhya Pradesh, over which this Court has power of superintendence, which were subsisting as on 10th March, 2021, shall stand extended till 15th June, 2021;
- (ii) that it is further directed that the interim orders or directions of this Court or any Court sub-ordinate to this Court in the State, which are not of a limited duration and were meant to operate

[4]

till further orders, shall continue to remain in force until modified/altered/vacated by specific order of the Court concerned in a particular case;

- (iii) that the time for filing of written-statement or return in any Suit or proceeding pending before any Civil Court or any other forum, unless specifically directed, shall stand extended till 15th of June, 2021. It is however clarified that this will not preclude the parties from filing such written-statement or return before 15th June, 2021;
- (iv) that it is further directed that the orders of eviction, dispossession, demolition, etc. passed by this Court or any Court subordinate to it or any Tribunal or Judicial or Quasi Judicial forum, which have so far remained unexecuted, shall remain in abeyance till 15th of June 2021;
- (v) that interim protection given in the anticipatory bail applications by the High Court or Court of Sessions for a limited period, which has expired or is likely to expire on any date after 10th March, 2021, shall stand extended till 15th of June, 2021. However, any party aggrieved by the conduct of the accused on such interim protection, may move the Court in seisin over the matter for discontinuation of such interim protection, if any prejudice is caused to him/her, in which event, the Court concerned shall be entitled to take independent view of the matter;
- (vi) that all the interim bail granted under Section 439, Cr.P.C. by the High Court or Courts of Sessions, limited by time-frame specifying an expiry on any date after 10th March 2021, shall stand extended till 15th June, 2021, subject to the accused not abusing such liberty or else it may be cancelled at the instance of the State or the complainant, on application with adequate proof of the abuse of the liberty so granted by the Court concerned;

- (vii) that parole granted to a person anytime after 9th March, 2021 by order passed by a Court exercising the criminal jurisdiction and limited by time-frame specifying an expiry date, shall stand extended till 15th of June, 2021, subject to the condition specified in Point No.(vi) above;
- (viii) that unless there is necessity of arrest for maintenance of law and order situation, in a cognizable offence prescribing sentence up to seven years imprisonment, the police shall desist from arresting the accused up to 15th of June, 2021, without complying with the provision of Section 41A, Cr.P.C. This however may not be understood as an interdict on the power of the police to arrest, but should only be considered mere advisory in the face of the ongoing crisis following second wave of Coronavirus;
- (ix) that the State Government or any of its Department or any Municipal Corporation / Council / Board or any Gram Panchayat or any other local body or any other agency and instrumentality of the State shall not take any action for eviction and demolition in respect of any property, over which any citizen or person or party or any Body Corporate, has physical or symbolic possession as on today till 15th June, 2021;
- (x) that it is further directed that, any Bank or Financial Institution shall not take action for auction in respect of any property of any citizen or person or party or any Body corporate till 15th June, 2021;
- (xi) that if the Government of Madhya Pradesh and/or any of its Department and/or functionaries, Central Government and/or its departments or functionaries or any Public Sector Undertakings or any Public or Private Companies or any Firm or any individual or person is/are, by the order of this Court or any Court subordinate to it or the Tribunals, required to do a particular thing or carry out certain direction in a particular manner, in a time frame, which has expired after 10th March,

[6]

2021 or is going to expire at any time from now up to 15th June, 2021, the time for compliance of such order shall stand extended up to 15th June, 2021, unless specifically directed otherwise by the Court concerned;

- (xii) that in order to dispel any ambiguity, it is clarified that:-
- (a) those interim orders / directions, which are not for a limited duration and are to operate until further orders, shall by this order remain unaffected;
 - (b) that, in case extension of interim order(s) as per the present order passed by this Court, causes any undue hardship and prejudice of any extreme nature, to any of the parties to such proceeding(s), such parties would be at liberty to seek appropriate relief by moving appropriate application(s) before the Competent Court(s), Tribunal, Judicial or Quasi-Judicial Forum, and these directions shall not be taken as a bar for such Courts/Forums to consider such application(s) filed by the aggrieved party, on its own merit, after due notice and providing opportunity of hearing to the other side;
 - (c) that the directions enumerated above shall not preclude the State from moving appropriate application for vacation/modification of such order in any particular case for reason of overriding public interest;
 - (d) that all Courts, Tribunals, Judicial and Quasi-judicial authorities are directed to abide by these directions, and the parties seeking relief(s) covered by these directions can file hard copy or soft copy of this order before the competent court/forum, which shall be given due weightage.

Registry is directed to prominently publish this order in the official website of the Court and circulate the same to all the Courts, Tribunals, judicial and quasi-judicial authorities of the State, over

[7]

which this Court has power of superintendence. A copy each of this order be endorsed to the learned Advocate General, learned Assistant Solicitor General for Madhya Pradesh and the Chairman of M.P. State Bar Council.

The Registry is directed to give wide publicity to this order through Print and Electronic Media having wide circulation in the State so that the litigants may know about the order and do not rush to the Court for different relief(s) covered by these directions.

Let notice of these proceedings be issued to the State of Madhya Pradesh through the Chief Secretary, Bhopal, through Advocate General and Union of India through the Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi and the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi, through the Assistant Solicitor General.

This Court hereby appoints Shri Aditya Adhikari, learned Senior Advocate as *Amicus Curiae* to assist the Court in the matter. A copy of this order be provided to him as well.

List this matter on **15th June, 2021** for further consideration.

(Mohammad Rafiq)
Chief Justice

(Sanjay Dwivedi)
Judge

S/

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म०प्र०

पृष्ठांक-1208 /विविध/2021
यथानिर्देशानुसार

विदिशा, दिनांक 24.04.2021

01. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा
02. समस्त न्यायिक अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विदिशा,
04. पुलिस अधीक्षक, विदिशा
06. जेल अधीक्षक जिला जेल एवं उपजेल गंजबासौदा/लटेरी
05. कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी विदिशा
06. अध्यक्ष अभिभाषक संघ विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. प्रिंट मीडिया/न्यूज मीडिया प्रमारी विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं सूचना प्रसारित किये जाने हेतु।
07. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/अस्सिस्टेंट को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश जिला न्यायालय विदिशा की वेबसाइट पर अपलोड करें।

वास्ते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा